स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–3, फाल्गुन–चैत्र 2068–69, मार्च 2012

सम्पादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

अनुक्रम

आवरण लेख
खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय सम्मेलन /4

अर्थव्यवस्था
वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के उपाय
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /10

दृष्टिकोण
सरकारी कर्ज के भंवर से बचे भारत
– डॉ. अश्विनी महाजन /12

सामयिकी
तेल के लिए खेल
– निरंकार सिंह /15

विचार–विमर्श
घटता निर्यात – चिंता का विषय
– जयंतीलाल भंडारी /18

अंतर्राष्ट्रीय : ईरान–इजरायल के बीच फंसा भारत
– बालेन्दु शर्मा 'दाधीच' /21

मुद्दा
केन्द्रीय नीति में राज्यों की सहमति जरूरी
– जवाहरलाल कौल /23

अधिकार
जनता के हक पर मोहर
– अरुण जेटली /26

पर्यावरण
हिमालय का विनाशकारी दोहन
– उमेश प्रसाद सिंह /28

यात्रा
भारत की आत्मा गाँव है एवं गाँव की आत्मा कृषक
– डॉ. नन्द सिंह नरूका /31

लेख
महिला शिक्षा और विकास
– रेणु पुराणिक /33

पाठकनामा / 2, रपट / 36

पाठकनामा

हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना होगा

स्वदेशी पत्रिका का फरवरी अंक पढ़ने को मिला बहुत ही पसंद इसलिए आया कि यह पत्रिका हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता व नैतिक शिक्षा के साथ–साथ आज की समस्याएं जैसे – पर्यावरण, भ्रष्ट तंत्र और इसके अतिरिक्त जीवन के सभी पहलुओं पर निरंतर प्रकाश डालती रहती है। आज हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है साथ ही हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसे प्रकृति का दोहन अपनी भोगविलासता के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मानव ने जितना प्रकृति का विनाश किया उसे सुधारने का कार्य करना चाहिए जैसे आवश्यकता से अधिक वाहन न रखना, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, पेड़ का संरक्षण के साथ साथ पेड़ लगाना, शहरों में बढ़ती जमीनी भूख को कम करना। इसके अलावा आज के हर व्यक्ति को अपनी भोग–विलासिता की भूख को छोड़ना होगा अन्यथा कही ऐसा न हो जाए कि मानव मानव का ही दुश्मन बन जाए।

– सुधीर रावत, फैबटेक सर्विस सेन्टर, अभय खण्ड–4, इंदिरापुरम्

राष्ट्रीय स्वाभिमान की सच्ची संवाहिका है स्वदेशी पत्रिका

मुझे स्वदेशी पत्रिका नियमित पढ़ने को मिल रही है। इसमें शामिल लेखों से मैं काफी प्रभावित हूँ। जनवरी 2012 के अंक में कहाँ से लाएगा केन्द्र अनाज, सिर्फ इच्छा नहीं इच्छा शक्ति चाहिए, सबसे बड़ा राजनीतिक छल, घरेलू महिलाओं का अवमूल्यन क्यों? आदि लेख बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा आपने मेरा लेख 'पानी पर सोचने का समय' छापा बहुत अच्छा लगा। स्वदेशी पत्रिका अब गाँव–गाँव तक सरस्वती शिशु मन्दिरों में पहुँच रही है और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि इसकी प्रसार संख्या निरंतर बढ़ती रहे। ताकि राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय जनजागरण में प्रगति आए।

– राजेन्द्र सिंह सोमवंशी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

दागियों से जनता दूर नहीं भागी

जनता चाहे जितनी जागी हो, चुनाव के दौरान अब भी दागियों से दूर नहीं भागी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब और उत्तराखण्ड में भी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लोगों ने जम कर वोट किया। बड़ी संख्या में ये जीते और इनमें से अधिकांश मामूली अंतर से दूसरे या तीसरे नम्बर पर रहे। उत्तराखण्ड में ऐसे दस शीर्ष उम्मीदवारों में से 70 फीसदी व पंजाब के दस शीर्ष उम्मीदवारों में से 50 फीसदी उम्मीदवार चुनाव में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे। वहीं यूपी में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 50 थी जिसमें से 18 ने शानदार जीत दर्ज की। इन परिणामों को देखकर लगता है कि जनता अभी भी आपराधिक और भ्रष्टतंत्र के जाल में फंसी हुई है। इसलिए जनता को जगाने के लिए अभी और मंथन की आवश्यकता है।

– राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, इंदिरापुरम

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मद्रोत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता स्वच्छ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

हम एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में गंभीर क्यों नहीं, जबकि सब जानते हैं कि आतंक का साया आज देश के लगभग हर राज्य पर मंडराने लगा है?

– जवाहरलाल कौल

उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास किया है और हम जनता के हितों के लिए काम करेंगे।

– अखिलेश यादव

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि केन्द्रीय सत्ता अब राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकेगी।

– प्रकाश सिंह बादल

देश में तकनीकी विकास तो हुआ लेकिन खुले में शौच करने का कलंक देश से अब तक नहीं मिटा।

– जयराम रमेश

मनमोहन सिंह सरकार ने अनायास ही अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ढकेल दिया है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

पूंजीवादी पैसे और सत्ता को अपना ईश्वर बना लेता है और फिर उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगभग सब कुछ कुर्बान कर देता है।

– निरंकार सिंह

अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हक के लिए इकट्ठा होना और धरने के माध्यम से प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल पहलू है।

– अरुण जेटली

लो शुरू हो गई सप्रंग विघटन की दास्तां

पांच राज्यो के विधानसभा चुनाव परिणाम ने देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि बजट बाद राजनीतिक दलों के बीच कुछ नए समीकरण बने। जाहिर है इस नए समीकरण में कांग्रेस का सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी नाम के दो राजनीतिक आइकॉन अपना असर खोने लगे है। यूपीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टिया एक एक कर कांग्रेस से दूरियां बनाने लगी हैं। तमिलनाडू में डीएमके और पश्चिम बंगाल में तृणमूल ने इशारों में नहीं खुलेआम कांग्रेस पर हमले बोल दिए हैं। इन दोनों पार्टियों की चाहत और कोशिश इस बात की है कि अगले किसी भी चुनाव में वे कांग्रेस के साथ न जाएं। इन दोनों पार्टियों के नेता अब कांग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ममता बनर्जी पहले भी एनडीए के साथ रह चुकी हैं, इसलिए उनके सम्पर्क सूत्र वहां उनके आने के इंतजार में हैं। डीएमके या एआईडीएमके पाले बदलने में जरा भी देरी नहीं करती। यह जग जाहिर है। अब उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की हार ने यूपीए के विघटन की नई पटकथा लिख दी है। अब केंद्र में कांग्रेस को समर्थन जारी रखने की मजबूरी न तो सपा की रही और न बसपा की। सत्ता से बेदखल के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती खुद राज्यसभा में पहुंच कर सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने वाली हैं। अब उनके सामने खोने को कुछ भी नहीं है। सीबीआई के जरिए भयादोहन कर अधिक दिनों तक समर्थन नहीं लिया जा सकता। सवा दो सौ विधायकों के साथ मुलायम सिंह इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वह खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे हैं। अपने पुत्र अखिलेश को मुख्यमत्री की कुर्सी सौप वह स्वयं तीसरे मोर्चे को जिंदा करने और लोकसभा चुनाव के मैदान में उसे उतारने की रणनीति पर लग चुके हैं। उनके सक्रिय होने का अर्थ ही हैं कांग्रेस के समर्थक दलों का छिटकना। रही सही कसर इस बार का बजट निकाल देगा। कांग्रेस के पास देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का आखिरी मौका है। पर आकड़े बताते हैं कि सरकार की हालत काफी पतली है। एक तरफ कर उगाही में भारी गिरावट आई है और दूसरी तरफ खर्चे में भारी बढोतरी। यानी घाटा बेशुमार। कांग्रेस के लिए मुसीबत ही यही है। यदि घाटा कम करने का प्रयास करते हैं तो आम जनता की परेशानी काफी बढ़ जाती है और आम जनता को राहत देने का प्रयास करते हैं तो अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ जाती है। इन दोनों में सामंजस्य बिठाने की हर कोशिश विफल होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपने लोकलुभावन नारों को चुनाव की बेला में छोड़ना नहीं चाहती, कर्ज माफी और मनरेगा ने वित्तीय संकट बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाई है और अब खाद्य सुरक्षा को लेकर वित्तमंत्री की बेचैनी बढ़ गई है। पर कांग्रेस के लिए इन मुद्दों को छोड़ने का विकल्प नहीं बचा है। अगले आम चुनाव में अपनी डूबती नइया को पार लगाने के लिए सोनिया गांधी के तरकश में ये आखिरी तीर हैं। पर ये तीर कहीं गलत निशाने पर न लगे इसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने में लगी है। यहां कांग्रेस और सरकार दोनों के लिए कठिनाइयां है। कुछ दिन थमने के बाद महंगाई फिर बढ़ने लगी है। पीछे महंगाई रोकने के जो उपाय रिजर्व बैंक के जरिए किए गए उसका दुष्परिणाम उद्योग व कॉरपोरेट जगत भुगत रहे हैं। औद्योगिक विकास दर सतह पर आ गई है और कॉरपोरेट जगत पूंजी के लिए ललायित हो रहा है। जाहिर है अब कोई भी कठोर मौद्रिक नीति देश की दशा बिगाड़ सकती है। सब तरफ से राहत की मांग की जा रही है। यदि बजटीय प्रावधानों से स्थिति नहीं सुधरती। आम आदमी का जीवन सरल नहीं होता तो उसका सारा प्रभाव यूपीए के स्थायित्व पर पड़ेगा। राजनीतिक दलों के बीच नए ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कांग्रेस अपने किए का भर रही है। कुछ समय से नीतियों को लेकर भी यूपीए बटा बटा सा नजर आ रहा है। खास कर खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को अनुमति देने के राहुल गांधी की जिद ने एक तरह से गठबंधन में दरार डाल दी है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर तो यूपीए छोड़ने को लगभग तैयार थी। उत्तर प्रदेश में भारी सफलता अर्जित करने वाले मुलायम ने भी कहा था कि यदि वालमार्ट या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टोर खुले तो वे आग लगा देंगे। कांग्रेस से छिटकने या उससे समर्थन वापस लेने का सिलसिला चल पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस के घटक दलों के बीच समन्वय नहीं के बराबर है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो राहुल गांधी को नेता के रूप में पेश करने की कांग्रेस की कोशिश को विफल माना जाएगा। यानी पवार भी पाला बदल सकते हैं। यूपीए घटक में कांग्रेस के लिए विश्वसनीय साथी का अभी से ही टोटा पड़ने लगा है। जिनको कांग्रेस के साथ चलने की मजबूरी है वे फिलहाल राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव व अजित सिंह जैसे नेता कांग्रेस के लिए कोई मजबूत विकल्प नहीं है। इनके बूते यूपीए का भविष्य नहीं बन सकता।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर राष्ट्रीय सम्मेलन

ग्रामीण भारत पहले ही खेती में संकट से जूझ रहा है। भारत की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती है क्योंकि यहां 82 प्रतिशत छोटे किसान हैं। इनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। इनका एक–चौथाई हिस्सा भूखा और बड़ा हिस्सा कुपोषित है। खेती का अर्थव्यवस्था में योगदान 50 प्रतिशत से गिरकर महज 14 प्रतिशत रह गया है जबकि आबादी का 62 प्रतिशत रोजगार अकेले खेती पर ही निर्भर है. ..

भारत के खुदरा कारोबार से जुड़े 31 से ज्यादा संस्थाओं ने एक साथ एक मंच पर एफडीआई का खुदरा कारोबार पर प्रभाव के ऊपर नई दिल्ली के जंतर–मंतर रोड के नजदीक एनडीएमसी कन्वेशन हॉल में 10 फरवरी को आयोजित किया।

अलग–अलग सत्रों में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स, किसान, यूनियन, और उपभोक्ताओं के अलग–अलग 800 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आयोजन समिति की ओर से सीएआईटी के महासचिव श्री प्रवीण खंडेलवाल ने सभी प्रतिनिधियों का तहे दिल से स्वागत किया। सीपीएम के वरिष्ठ नेता श्री बासुदेव आचार्य ने कन्वेशन का उदघाटन दीप प्रज्ज्वलित करके किया। सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भाई शाह भी सम्मेलन में मौजूद थे।

प्रारंभिक सत्र के आरंभ में देश के प्रमुख किसान नेता श्री नरेश सिरोही ने कहा कि इस मुददे के महत्व को देखते हुए खुदरा कारोबार से जुड़े हिस्सेदारों ने तय किया है कि इसके लिए एक साझा मुहिम चलाई जाए। खुदरा कारोबार खेती के बाद देश में सबसे बड़ा नियोजक है। देश में किसानों को दी जाने वाली बहुत बड़ी सब्सिडी इस बात का गवाह है कि एफडीआई से किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। इससे दुनियाभर के किसान तबाह हो रहे है।

कन्वेशन को संबोधित करते हुए सीपीएम के वरिष्ठ नेता और सांसद श्री बसुदेव आचार्य ने कहा कि यह मुददा सुर्खियों में तब आया जब यूपीए–1 में सरकार ने सिंगल ब्रांड रीटेल में 51 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी थी और सरकार इंश्योरेंस में 49 फीसदी एफडीआई लाने की फिराक में थी। यह फैसला देश के 40 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करने वाला है और इस पर सरकार ने संसद को अंधेरे में रखा। ग्रामीण भारत पहले ही खेती में संकट से जूझ रहा है। भारत की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती है क्योंकि यहां 82 प्रतिशत छोटे किसान हैं। इनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। इनका एक–चौथाई हिस्सा भूखा और बड़ा हिस्सा कुपोषित है। खेती का अर्थव्यवस्था में योगदान 50 प्रतिशत से गिरकर महज 14 प्रतिशत रह गया है जबकि आबादी का 62 प्रतिशत रोजगार अकेले खेती पर ही निर्भर है। भारत की तुलना चीन से नहीं की जा सकती है क्योंकि भारत सरकार का मकसद गरीबों की भलाई करना है। सरकार खुदरा कारोबार में जिसे विदेशी निवेश का हवाला दे रही है वह विश्वास के काबिल नहीं है क्योंकि विदेशी पूंजी को कभी भी वापिस लिया जा सकता है। सरकार तो पहले से ही रोजगार दिला पाने में असमर्थ है और स्व–नियोजित सेक्टर को बर्बाद करने में लगी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में फर्क बढ़ता जा रहा है। पूर्वी एशिया के उदाहरण से भी यह साफ है कि एफडीआई से किसानों का भला नहीं होने वाला है। कॉरपोरेट किसानों को बर्बाद कर देंगे। 1991 के बाद उदारवाद से खेती पहले से ही संकट में है। हमें इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए जन–आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है।

इस संबोधन के साथ ही प्रारंभिक सत्र समाप्त हो गया। इसके बाद आर्थिक सत्र का आरंभ हो गया जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी, फॉरवर्ड ब्लॉक के देबब्रत विश्वास और अमूल के मैनेजिंग डॉयरेक्टर श्री आर. एस सोढी ने हिस्सा लिया।

आर्थिक सत्र

इस विषय पर बहस आरंभ करते हुए

मुंबई के खुदरा व्यापार विशेषज्ञ श्री एस वी फेन ने खुदरा कारोबार में एफडीआई के प्रभाव को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। क्योंकि ये खुदरा कारोबार से जुड़े करोड़ो लोगों के हितों के लिए प्रतिकूल साबित होगा। उन्होंने इस विषय पर किए गए दूसरे देशों के अनुभवों का हवाला दिया जहां कि वैश्विक खुदरा कारोबारी बड़ा कारोबार चला रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और संसाधनों के बल पर खुदरा कारोबार को अपने नियंत्रण में कर लेती हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने अफसोस जताया कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी जोरदार लॉबिंग कई बड़े किसानों और दूसरे संगठनों को अपने हित मे बोलने के लिए राजी कर लिया है।

खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश किसानों, छोटे खुदरा कारोबारियों और देश तीनों के लिए समान रूप से खतरनाक है। इस नीति से यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान सरकार गरीबों के हितों के प्रति कितनी उदासीन है। उन्होंने कहा कि हम तकनीक और आधुनिकता के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अस्तित्व की रक्षा के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सम्मेलन दूसरे राज्यों में भी आयोजित होने चाहिए।

खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश किसानों, छोटे खुदरा कारोबारियों और देश – तीनों के लिए समान रूप से खतरनाक है। इस नीति से यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान सरकार गरीबों के हितों के प्रति कितनी उदासीन है। हम तकनीक और आधुनिकता के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अस्तित्व की रक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।

– श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', स्वदेशी जागरण मंच

जानेमाने अर्थशास्त्री मोहन गुरूस्वामी ने सम्मेलन को सबोधित करते हुए कहा कि ये विदेशी निवेश के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हैं लेकिन वैश्विक खुदरा व्यापारियों का कारोबारी मॉडल मोनोपॉलिस्ट बनाता है। अध्ययन से यह साबित हो जाता है कि बड़ी खुदरा कंपनियां थोक भाव से बड़े पैमाने पर खरीद करती हैं इससे खेत से जुड़े उत्पादों की कीमतें कम हो जाती हैं और वालमार्ट जैसी कंपनियां जहां भी गई हैं वहां से परंपरागत बाजार खत्म हो गए हैं और बड़ी कंपनियों का एकाधिकार हो गया है। एकाधिकारवादी खरीदार ही एकाधिकारवादी विक्रेता बन जाते हैं। वालमार्ट के कुल स्टॉक का 90 फीसदी चीन से आता है।

इसका सालाना टर्नओवर 422 अरब डॉलर का है और चीन से होने वाले आयात करीब 80 अरब डॉलर का है। इसलिए चीन से मंगाया जाने वाला हिस्सा उसके फायदे का बड़ा हिस्सा है। वालमार्ट अपने मोनोपॉलिस्ट ताकत से मजदूरी की दर को कम करता है। वह अपने सप्लायर पर दबाव बनाता है कि वे उत्पादों की कीमतें कम करें और जाहिर है कि इससे उत्पादक मजदूरों को कम मजदूरी देने के लिए मजबूर होते हैं।

जैसा कि चीन के बाजारों में देखने को मिल रहा है और यह जानकर तो और भी हैरानी होती है कि सरकार को इस बात की चिंता नहीं कि बेरोजगारों को नौकरी कैसे दे बल्कि वह वैश्विक खुदरा व्यापार में विदेश निवेश को लेकर ज्यादा चिंतित है। उन्होंने इस मुद्दे पर खुली बहस के लिए किसी बड़े मंच के नहीं होने पर भी दुख जताया।

अफसोसजनक बात तो यह है कि इस मुद्दे जुड़ा हर भागीदार अपने ही बारे में सोच रहे हैं उन्हें देश और किसानों की चिंता नहीं है। भारत में खराब भंडारण व्यवस्था का तर्क कमजोर है क्योंकि विकासशील देशों में अनाज की बर्बादी विकसित देशों की तुलना में कम है।

स्वदेशी जागरण मंच के श्री अश्विनी महाजन ने कहा कि सरकार ने खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का फैसला बिलकुल एकतरफा है। व्यापारी, किसान और खुदरा कारोबार से जुड़े बाकी लोग भी इस तरह के विदेशी निवेश के पूरी तरह से खिलाफ हैं। इसका समर्थन वही लोग कर रहे है जिनका इसमें अपना निहित स्वार्थ है। विकसित देशों के अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि वैश्विक खुदरा कारोबार से किसानों का कभी भला नही हुआ है। अमरीका में खाने–पीने की चीजों का खुदरा कारोबार बढ़कर 1200 अरब डॉलर हो गया जबकि 2000 में यह

सरकार द्वारा खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का फैसला बिलकुल एकतरफा है। व्यापारी, किसान और खुदरा कारोबार से जुड़े बाकी लोग भी इस तरह के विदेशी निवेश के पूरी तरह से खिलाफ हैं। इसका समर्थन वही लोग कर रहे है जिनका इसमें अपना निहित स्वार्थ है। विकसित देशों के अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि वैश्विक खुदरा कारोबार से किसानों का कभी भला नही हुआ है।

– डॉ. अश्विनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच

खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का मतलब सिर्फ यही है कि खानेपीने की चीजों के कारोबार का वैश्वीकरण। विदेशी खुदरा कारोबार भारत के छोटे खुदरा कारोबार के साथ कभी नहीं रह सकता है जो बड़े खुदरा कारोबारी हैं वे बड़ी सोच–समझ कर नीति बनाते हैं और ताकतवर लॉबिंग से सिस्टम को प्रभावित करते हैं।

– श्री शेखर स्वामी, विख्यात लेखक

आकड़ा महज 833 अरब डॉलर था। जबकि किसानों के खानेपीने की चीजों की बिक्री 25 फीसदी घट गई।

अमरीका के किसान भारत के किसानों से भी कम मुनाफा कमाते हैं। भारत में खाने–पीने की चीजों को जानबूझ कर बर्बाद किया जाता है कि ताकि इस बात पर जोर डाला जा सके इनके बेहतर रख–रखाव के लिए कोल्ड–स्टोरेज बनाने के लिए भारत में एफडीआई आवश्यक है। कोल्ड–स्टोरेज के लिए सरकार के पास 7800 करोड़ रुपये की कमी का बहाना काफी कमजोर है क्योंकि इतना पैसा तो घरेलू आमद में आराम से जुटाया जा सकता है।

किसान जागृति मंच (लखनऊ) के श्री सुधीर पनवर ने कहा कि बिना किसी बहस के ही इतना बड़ा फैसला ले लिया है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। सभी अध्ययनों से यह साबित होता है कि खुदरा कारोबार से जब भी विदेशी निवेश को जोड़ा गया है तो इससे बेरोजगारी में इजाफा होता है। देश पूरी तरह से भंडारण सुविधाओं के विस्तार के लिए रकम जुटाने में समर्थ है लेकिन वर्तमान समय में जो अफरातफरी के हालात हैं उसके लिए सरकारी नीतियां और कुव्यवस्था ही जिम्मेदार है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की मौजूदा हालत को सुधारा जाए और उनके लगातार गिरते सालाना आमदनी पर भी चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक भारत में कारोबार सिर्फ कमाने का ही जरिया नहीं है बल्कि जिंदगी चलाने का माध्यम है।

मुंबई के विख्यात लेखक श्री शेखर स्वामी ने कहा कि खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का मतलब सिर्फ यही है कि खानेपीने की चीजों के कारोबार का वैश्वियकरण। विदेशी खुदरा कारोबार भारत के छोटे खुदरा कारोबार के साथ कभी नहीं रह सकता है जो बड़े खुदरा कारोबारी हैं वे बड़ी सोच–समझ कर नीति बनाते हैं और ताकतवर लॉबिंग से सिस्टम को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने मैक्सिको का उदाहरण दिया जिसने 1994 में नॉर्थ अमरीका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था जिसके तहत मैक्सिको का बाजार पूरी तरह से खोल दिया गया लेकिन श्रम बाजार नहीं खुला जिससे मैक्सिको के खुदरा कारोबार पर कॉरपोरेट कब्जा हो गया जबकि 25 फीसदी से ज्यादा किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए। गैरकानूनी पलायन दोगुना हो चुका है और लोगों को विस्थापन बड़ा रूप ले चुका है।

उनके मुताबिक भारतीय बाजार काफी हद तक विकेंद्रित है और कोई एकाधिकार नहीं है लेकिन वैश्विक कारोबारियों के आने से हालात बदल जाएंगे और कीमतें भी बढ़ेंगी। भारत में फिलहाल लघु उद्योगों से ही 60 फीसदी सामान खरीदे जाते हैं जबकि विदेशी निवेश में यह 30 फीसदी ही है। इसका मतलब साफ है कि बाकी सामान विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश देश के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जानीमानी कृषि विशेषज्ञ वंदना शिवा ने कहा कि किसानों का मोहरा बनाकर सरकार इस नीति को लागू करना चाहती है जबकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश आजादी और सच्चाई पर हमला है। बड़ी कंपनियां उत्पाद और आपूर्ति के सामान्य संबंधों का गला घोट देगीं। उन्होंने अफसोस जताया कि कोई भी विश्वसनीय किसान संगठन इस नीति का समर्थन नहीं किया है जबकि सरकार किसानों की आड़ में इस नीति को लागू करने की फिराक में है।

एक मजबूत खेती आधारित व्यवस्था खुदरा कारोबार की रीढ होती है। ये नीति किसानों को फायदा नहीं पहुचाने वाली है। जैसा कि मोनसेन्टो के मामले में देखा गया है जैसे ही इस कंपनी ने बीज कारोबार में कदम रखा तब से लेकर 2,50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

किसानों को मोहरा बनाकर सरकार इस नीति को लागू करना चाहती है जबकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश आजादी और सच्चाई पर हमला है। बड़ी कंपनियां उत्पाद और आपूर्ति के सामान्य संबंधों का गला घोट देगीं। उन्होंने अफसोस जताया कि कोई भी विश्वसनीय किसान संगठन इस नीति का समर्थन नहीं किया है जबकि सरकार किसानों की आड़ में इस नीति को लागू करने की फिराक में है।

– डॉ. वन्दना शिवा, कृषि विशेषज्ञ

यह तर्क कि बिचौलिए के नहीं होने से महंगाई में कमी आएगी–खुद में ही कमजोर तर्क है। क्योंकि बिचौलिए की जगह पर बड़े कारोबारी ले लेते हैं जिनका पेट बड़े मुनाफे से ही भरता है। हायपर मार्केट से गुणवत्ता, विविधता और स्वाद खत्म हो जाता है। स्वादिष्ट अनाज बर्बाद हो जाते हैं। बड़े कारोबारियों के उच्च–मानकीकरण से स्वाद और गुणवत्ता में कमी आती है। इसके बाद जीन–प्रसंस्कृत खादय सामग्री की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है जो लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है।

भारत तो सनड्राई फूड–स्टोरेज के लिए जाना जाता था जहां कि रेफ्रीजरेशन की आवश्यकता न के बराबर है। रेफ्रीजरेशन जलवायु के लिए भी खतरनाक है। भारतीय औरतें फूड–स्टोरेज में माहिर हैं इसलिए हमें किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है। बड़े कारोबारी हमारे संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करते हैं।

राजनीतिक सत्र

फॉरवर्ड ब्लॉक के सांसद श्री देवव्रत विश्वास ने इस लड़ाई में सबको एकजुटता की मांग करते हुए कहा कि समाजवादी और वाम धड़ा तो पूरी तरह खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के खिलाफ एकजुट है। क्योंकि विदेशी निवेश एक तरह से विदेशी शासन की तरह है। हम अपने खेत, पानी और वातावरण पर से भी अधिकार खो देंगे। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब लोकतांत्रिक सरकार की जगह कंपनी सरकार चल रही है जो सिर्फ कॉरपोरेट के मुनाफे के अलावा कुछ नहीं सोचती है। संसद को ताक पर रख दिया है। सरकार यह वकालत कर रही है कि राज्य इस नीति से खुद को अलग रखने को आजाद होंगे लेकिन वो यह बात भूल रही है कि भारत एक देश है। यह सच नहीं है कि बड़े आकार के खेत में ज्यादा उत्पादन होता है।

सच्चाई यह है कि छोटे आकार के खेत ही ज्यादा उपज देते हैं और ऐसे खेतों का हिस्सा 80 फीसदी है। उन्होंने सरकार से यह सवाल किया कि वह खुद क्यों नहीं आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए निवेश करती है जिसके लिए विकसित तकनीक की जरूरत नहीं है इसे स्वदेशी तकनीक से ही विकसित किया जा सकता है। उनके विचार से भारत में खेती के बेहतर विकास के लिए बेहतर बाजार और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने खुदरा कारोबारियों के बीच बेहतर नेटवर्क बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि खुदरा कारोबार को परंपराओं से जोड़ने की आवश्यकता है।

अमूल के एमडी आर. एस. सोढ़ी ने माना कि विकसित देश में विदेशी किसान खुदरा कारोबार में मल्टीनेशनल के आने से नुकसान में ही रहे हैं। अगर किसी भी देश में फूड–चेन को नियंत्रित कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि पूरा देश पर कब्जा। भारत में अगर मल्टी–ब्रांड रीटेल की अनुमति दी जाती है तो यहां के डेयरी किसान भी वैसे ही संघर्ष करेंगे जैसा कि विदेशों में देखने का मिल रहा है। वैश्विक रीटेल चेन से भारतीय बाजार को जोड़ने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारतीय उपभोक्ता और किसान विदेशी उथल–पुथल से प्रभावित होने लगेंगे। अमरीका में डेयरी किसान की बिक्री 1996 में 52 प्रतिशत से घटकर 2009 में 38 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह से यूके में 56 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत रह गया है।

विकसित देश में विदेशी किसान खुदरा कारोबार में मल्टीनेशनल के आने से नुकसान में ही रहे हैं। अगर किसी भी देश में फूड–चेन को नियंत्रित कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि पूरा देश पर कब्जा। भारत में अगर मल्टी–ब्रांड रीटेल की अनुमति दी जाती है तो यहां के डेयरी किसान भी वैसे ही संघर्ष करेंगे जैसा कि विदेशों में देखने का मिल रहा है।

– श्री आर.एस. सोढी, एमडी अमूल

जिस तरह से आज देश में वैश्विक साजिश हो रही है जिससे गरीबों का ही खात्मा हो जाए। सारी सरकारें अमरीकापरस्त होती जा रही हैं। खुदरा कारोबार में एफडीआई ऐसा ही मुद्दा है। हमें सरकार पर इस तरह की नीतियों के खिलाफ दबाव बनाना चाहिए।

– श्री संजय पासवान, पूर्व सांसद

उन्होंने यह भी कहा कि बिचौलिए के मुनाफे का आंकड़ा भी गलत और आधारहीन है। भारत छोटे कारोबारियों का देश है और इसे इसी तरीके से रहना चाहिए।

भारत कृषक समाज के प्रेसिडेंट डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि अगर सरकार सचमुच किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है तो उसे अपनी नीतियों की दिशा बदल देनी चाहिए। हमें विदेशी अनुदान की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। देश में ही को–ऑपरेटिव के सफल उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे ही मॉडल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा है जबकि भारत इस तरह के संकट से अब भी बचा हुआ है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे किसान और कारोबारी हैं। यह मॉडल हजारों साल से चला आ रहा है और कारगर है। वैश्विक कारोबारियों के लिए यह एग्री–बिजनेस है जबकि हमारे लिए यह परंपरा और संस्कृति है। खुदरा में विदेशी निवेश के खतरनाक अंजाम होंगे। – डॉ. मुरली मनोहर जोशी, भाजपा

जेनेटिकली मॉडिफायड फूड के जरिए कृत्रिम रंग, स्वाद और ग्रेड को जन्म दिया जाता है और इसमें किसानों का शोषण होता है।

पूर्व सांसद श्री संजय पासवान ने कहा कि इस तरह की वैश्विक साजिश हो रही है जिसमें गरीबों का ही खात्मा हो जाए। सारी सरकारें अमरीकापरस्त होती जा रही हैं। खुदरा कारोबार में एफडीआई ऐसा ही मुद्दा है। हमें सरकार पर इस तरह की नीतियों के खिलाफ दबाव बनाना चाहिए।

वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि खुदरा कारोबार में एफडीआई के खिलाफ संघर्ष में वे शामिल रहे हैं। अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा है जबकि भारत इस तरह के संकट से अब भी बचा हुआ है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे किसान और कारोबारी हैं। यह मॉडल हजारों साल से चला आ रहा है और कारगर है। वैश्विक कारोबारियों के लिए यह एग्री–बिजनेस है जबकि हमारे लिए यह परंपरा और संस्कृति है। खुदरा में विदेशी निवेश के खतरनाक अंजाम होंगे। यह देश के संसाधनों पर कब्जे की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत किसी तरह का शर्त नहीं रखा जा सकता है। इसलिए 30 फीसदी का कोटे की बात ही बेमानी है। इन विदेशी खुदरा कारोबारियों का विरोध तो विकसित देशों में भी हो रहा है। यह वालस्ट्रीट आंदोलन की शक्ल में निकल रहा है। उनकी नीति ही यही है सस्ता से सस्ता खरीद कर महंगा से महंगा बेचना। स्वतंत्र तरीके से खेती करना हमारी अर्थव्यवस्था की जान है इसलिए इसे हर हाल में बचाने की आवश्यकता है।

भागीदारी सत्र

नेशनल हॉकर्स असोसिएशन के महासचिव श्री शक्तिमान घोष ने कहा की इससे देश के हर सेक्टर को नुकसान होगा। हॉकर्स सबसे ज्यादा माल लघु–उद्योगों से खरीदते हैं। 80 फीसदी सब्जियां देश में हॉकर्स ही बेचते हैं। हॉकर 1000 कैलोरी सिर्फ 7 रूपये में प्रदान करता है। वैश्विक खिलाड़ियों के आने से कीमतों में इजाफा होगा और हॉकर्स और छोटे कारोबारी बुरी तरह प्रभावित होंगे हमें इनकी हितों की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है।

ग्रामीण स्वाभिमान के राजस्थान चैप्टर के प्रसिडेंट श्री भागीरथ चौधरी ने इसे गरीब भारत को और भी गरीब बनाने की साजिश करार दिया। सरकार जानबूझकर स्टेकहोल्डर्स के बीच भ्रम पैदा कर रही है और हमें इस मंशे को समझने की आवश्यकता है।

भारतीय मजदूर संघ के श्री पवन कुमार ने हमें विदेशों के अनुभवों से सीख लेने की आवश्यकता है जहां खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के कुपरिणाम साफ दिख रहे हैं। विडंबना यह है कि जब भी विश्व व्यापार संगठन से समझौता होता है तो संसद को अंधेरे में रखा जाता है। उन्होंने खुदरा कारोबारियों और किसानों के हितों के लिए विदेशी निवेश के विरोध करने पर जोर दिया। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की सरकारी नीतियों के खिलाफ 28 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है और इसमें देश के कई बड़ी यूनियनें समर्थन करेंगी।

भारत उद्योग व्यापार मंडल के श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सरकार छोटे कारोबारी, किसान और उपभोक्ता के बीच कायम विश्वास के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। उसका सारा जोर कॉरपोरेट को समर्थन करने का है ताकि उनका मुनाफा बढ़े। जबकि सरकार को छोटे किसानों की मदद के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

जर्मन कैथोलिक बिशप आर्गेनाईजेशन फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन मिसरर के श्री अरमीन पाश्च ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त कारोबार से काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र में 30 लाख से 60 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। हॉकर्स राईट टू फूड पर गंभीर असर पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र का खुदा कारोबार में हिस्सा 90 फीसदी से घटकर 55 फीसदी रह जाएगा। मैक्सिको और अर्जेंटिना के अनुभव बताते हैं कि सुपर मार्केट सिर्फ महंगी खाने की चीजे बेचते हैं और इसका नकारात्मक असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

किसान महापंचायत के अध्यक्ष श्री रामपाल जाट ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। किसानों को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए किसानों ने 26 फरवरी जयपुर में रैली भी की है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंघल के मुताबिक यह तर्क कि एफडीआई से आधारभूत संरचना के विकास का दावा खोखला है। दरअसल सरकार की नीतियों में ही खामी है। इससे उत्पादों की कीमतें

किसान तो हमेशा से दुख झेलते आए हैं और व्यापारियों की भी अब यही स्थिति है। बिजली, तेल और परिवहन लागत बढ़ चुकी है लेकिन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने को तैयार नहीं है। यही हालात रहे तो किसान भारत से विलुप्त हो जाएंगे।

– श्री नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन (उ.प्र.)

नहीं कम होने वाली है क्योंकि अभी तो किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस लड़ाई में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया।

नोएडा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राईजेज के श्री. पी.सी. कोसी के मुताबिक इस समस्या से विकसित और विकासशील देश दोनो ही बराबर प्रभावित हैं जो अब अरब देशों और बाकी देशों में भी दिख चुका है। उन्होंने सरकार से मांग कि है कि वह खुदरा व्यापार की आधिकारिक परिभाषा दें और एक व्यापक खुदरा व्यापार नीति देश के लिए बनाए। छोटे उद्योग और खुदरा कारोबार को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया।

ग्राहक पंचायत के श्री ओ पी. सचदेव ने ब्रिटेन के आउटलुक मैगजीन का हवाला देते हुए कहा कि टेस्को खाने–पीने के खुदरा कारोबार पर 76 फीसदी कब्जा है। खेती लायक वातावरण होने के बाद भी आज ब्रिटेन अमेरिका और न्यूजीलैंड से खाद्यान्न आयात करने को मजदूर है। वैश्विक रीटेल कारोबारी आलू तो 5 रूपये प्रति किलो खरीदते हैं लेकिन चिप्स 100 रूपये किलो बेचते हैं।

भारतीय किसान संघ के महासचिव श्री प्रभाकर राव केलकर के मुताबिक विदेशी निवेश प्रतिस्पर्धा खत्म कर देगा और मध्यप्रदेश का आईटीसी का हरियाली बाजार इसका बेहतरीन उदाहरण है। हमें सभी एमएनसी और उनके उत्पादों का विरोध करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के श्री नरेश टिकैत के मुताबिक किसान तो हमेशा से दुख झेलते आए हैं और व्यापारियों की भी अब यही स्थिति है। बिजली, तेल और परिवहन लागत बढ़ चुकी है लेकिन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने को तैयार नहीं है। यही हालात रहे तो किसान भारत से विलुप्त हो जाएंगे।

किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री ओमप्रकाश धनखड़ के मुताबिक भारत की संप्रभुता के लिए फूड–सिक्योरिटी अहम है। सरकार की नीतियों के कारण किसान लगातार गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्यों खाद्य पदार्थों की कीमतें तय की जाती हैं और किसानों को कम पैसे दिए जाते हैं। उनके मुताबिक हर क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ लेकिन खेती को हमेशा नजरअंदाज किया गया। ऐसे में वैश्विक खुदरा कारोबारियो से भारत का भला नहीं होने वाला है।

सरकार काफी समय से रीटेल में विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन घरेलू कारोबारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक संप्रभुता बचाने के लिए आर्थिक संप्रभुता संरक्षित करना आवश्यक है। वायदा बाजार कॉरपोरेट के लिए तो अच्छा है लेकिन किसानों के लिए खतरनाक है।

– श्री मुरलीधर राव, महासचिव भाजपा

भाजपा के महासचिव श्री मुरलीधर राव ने कहा कि सरकार काफी समय से रीटेल में विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन घरेलू कारोबारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक संप्रभुता बचाने के लिए आर्थिक सप्रभुता संरक्षित करना आवश्यक है। वायदा बाजार कॉरपोरेट के लिए तो अच्छा है लेकिन किसानों के लिए खतरनाक है। वैश्विक खुदरा कारोबारियों के आने से महंगाई कम होगी ऐसा कहना हास्यास्पद है। उन्होंने मिलजुलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।

सीएआईटी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री बी. सी. भारतीय ने सम्मेलन के समापन सत्र में सबकी ओर से कहा कि एफडीआई ज्वलंत मुद्दा है जिसका जीताजागता सबूत है कि इतने सारे स्टेकहोल्डर्स एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं।

उन्होंने सभी भागीदारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त समिति बनाने की घोषणा की। इस तरह के राज्य–स्तरीय सम्मेलन सभी राज्यों में आयोजित होंगे और संयुक्त समिति के प्रतिनिधि अलग–अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अलग–अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर ज्ञापन देंगे। संयुक्त समिति बहुत जल्द इस बात का फैसला करेगी कि भविष्य में किस तरह की रणनीति अपनानी है।

– प्रस्तुति प्रवीन खंडेलवाल

वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के उपाय

मनमोहन सिंह सरकार ने अनायास ही अर्थव्यवस्था को गड्ढे मे ढकेल दिया है। टैक्स पालिसी को जन–कल्याण का अस्त्र बनाने के स्थान पर केवल आय बढ़ाने का साधन बना दिया है। इस आय का रिसाव हो रहा है। अतः वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का सीधा रास्ता भ्रष्टाचार पर सख्ती एंव आर्थिक पालिसियों को जन–कल्याण की तरफ मोड़ना है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने स्वीकार किया है कि सरकार का वित्तीय घाटा पूर्वानुमान से बहुत अधिक होगा। पहला कारण है कि इस वर्ष सरकार को विनिवेश से पर्याप्त रकम नहीं मिली है। पिछले वर्ष स्पेक्ट्रम की बिक्री से लगभग 100 हजार करोड़ रूपये मिले थे जिससे घाटा कम हो गया था। खर्च पिछले वर्ष भी बढ़े थे परन्तु ये दिखाई नहीं पड़े चूंकि आय भी बढ़ गई थी। परन्तु स्पेक्ट्रम की बिक्री जैसी आय कई दशकों में एक बार होती है। इस वर्ष ऐसी आय न होने के कारण बढ़े हुए खर्च दिखने लगे हैं। इन्हें पोषित करने के लिए सरकार को ऋण लेने पड़े हैं और वित्तीय घाटा बढ़ रहा है।

वित्तीय घाटे के बढ़ने का दूसरा कारण सब्सिडी मे वृद्धि है। सरकार ने पेट्रोल के दाम वैश्विक दाम से जोड़ दिये हैं परन्तु डीजल पर सब्सिडी जारी है जिससे यह भार बढ़ रहा है। खाद्यान्न सब्सिडी तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर भी खर्च बढ़ रहा है।

तीसरा कारण बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। सरकारी राजस्व का उपयोग सड़क आदि बनाने के लिए किया जाए तो दोहरा लाभ होता है। श्रम एवं सीमेंट आदि की मांग पैदा होती है। साथ–साथ अच्छी सड़क उपलब्ध होने से ढुलाई का खर्च कम पड़ता है। उसी राजस्व को स्विस बैंक मे जमा करा दिया जाए तो देश की क्रयशक्ति कम होती जाती है। देश मे मंदी आती है जिससे तोड़ने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है और वित्तीय घाटा बढ़ता है।

वित्तीय घाटे का सिद्धांत है कि किन्ही कठिन परिस्तिथियों मे अर्थव्यवस्था को झटका लगे तो उससे उबारने के लिए कुछ समय के लिए सरकारी खर्च बढ़ा दिए जाए। वाइरल फीवर से पीड़ित व्यक्ति को कुछ समय के लिए टोनिक दे दिया जाए तो वह पुनः काम पर जाने को खड़ा हो

वित्तीय घाटे के बढ़ने का दूसरा कारण सब्सिडी मे वृद्धि है। सरकार ने पेट्रोल के दाम वैश्विक दाम से जोड़ दिये हैं परन्तु डीजल पर सब्सिडी जारी है जिससे यह भार बढ़ रहा है। खाद्यान्न सब्सिडी तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर भी खर्च बढ़ रहा है। तीसरा कारण बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। सरकारी राजस्व का उपयोग सड़क आदि बनाने के लिए किया जाए तो दोहरा लाभ होता है। श्रम एवं सीमेंट आदि की मांग पैदा होती है। साथ–साथ अच्छी सड़क उपलब्ध होने से ढुलाई का खर्च कम पड़ता है।